ब्रह्म प्रकाश शर्मा और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

[पतंजलि शास्त्री सी. जे., मुखर्जीया, एस. आर. दास, गुलाम हसन और भगवती जे.]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1926 - न्यायिक अधिकारियों के आचरण या चरित्र पर प्रतिबिंब-जब न्यायालय की अवमानना के बराबर होता है। अवमानना की कार्यवाही-मार्गदर्शक सिद्धांत-जिन मामलों को दरकिनार किया जाना चाहिए-आसपास की परिस्थितियों की प्रासंगिकता-क्षेत्राधिकार का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।

(1) वाघोजी बनाम। कामाजी, आई. एल. आर. 29 बम। 249 .

अवमानना कार्यवाही का उद्देश्य न्यायाधीशों को व्यक्तिगत रूप से उन आरोपों से सुरक्षा प्रदान करना नहीं है जिन पर वे व्यक्तिगत रूप से उजागर हो सकते हैं, बल्कि इसका उद्देश्य जनता के लिए एक सुरक्षा होना है जिसका हित बहुत अधिक प्रभावित होगा यदि किसी भी पक्ष के कार्य या आचरण से न्यायालय का अधिकार कम हो जाता है और उसके द्वारा न्याय के प्रशासन में लोगों के विश्वास की भावना कमजोर हो जाती है।

जब स्वयं न्यायालय पर हमला किया जाता है, तो अवमानना कार्यवाही के माध्यम से संक्षिप्त अधिकार क्षेत्र का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और केवल तभी जब मामला स्पष्ट और उचित संदेह से परे हो।

ऐसे मामलों में दो प्राथमिक विचार हैं जिन पर अदालत को विचार करना चाहिए, पहला कि क्या न्यायाधीश के आचरण या चरित्र पर प्रतिबिंब निष्पक्ष और उचित आलोचना की सीमा के भीतर है, और दूसरा, क्या यह केवल न्यायाधीश की मानहानि या मानहानि है या अदालत की अवमानना के बराबर है। यदि यह न्यायाधीश पर केवल मानहानिकारक हमला है और इस तरह के न्यायालय द्वारा न्याय के उचित पाठ्यक्रम या कानून के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए गणना नहीं की जाती है, तो अवमानना के माध्यम से आगे बढ़ना उचित नहीं है।

जहां यह सवाल उठता है कि क्या किसी न्यायाधीश के खिलाफ निर्देशित मानहानिकारक बयान की गणना न्यायाधीश की क्षमता या अखंडता में जनता के विश्वास को कम करने के लिए की जाती है या अदालत को अपने कर्तव्यों के सख्त और अनिच्छुक प्रदर्शन से विचलित करने की संभावना है, आसपास के सभी तथ्य और परिस्थितियां जिनके तहत बयान दिया गया था और उसे दिए गए प्रचार की मात्रा प्रासंगिक

परिस्थितियां होंगी। प्रश्न का निर्धारण केवल भाषा या दिए गए कथन की सामग्री के संदर्भ में नहीं किया जाना है।

जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति को न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिले के राजस्व अधिकारी द्वारा मामलों का निपटारा करने और वादियों और वकीलों के प्रति व्यवहार करने के तरीके के खिलाफ कई शिकायतें मिलीं, और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि "यह उनकी सुविचारित राय थी कि दोनों अधिकारी कानून में पूरी तरह से अक्षम हैं, अपने न्यायिक कार्य में विश्वास पैदा नहीं करते हैं, आदेश पारित करते समय गलत तथ्यों को बताने के लिए दिए जाते हैं और वादी जनता और वकीलों के लिए समान रूप से अपमानजनक और अपमानजनक होते हैं" और अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न शिकायतों की एक सूची दी। यह प्रस्ताव कैमरे में पारित किया गया था, जिसे स्वयं राष्ट्रपति ने टाइप किया था और जिला मजिस्ट्रेट को गोपनीय रूप से भेजा गया था। प्रभाग के आयुक्त, और राज्य के मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री। जिला मजिस्ट्रेट ने अदालत की अवमानना के लिए प्रस्ताव पारित करने वाले अपीलार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी अवमानना के दोषी थे, लेकिन उनकी माफी स्वीकार कर ली।

अपील पर अभिनिर्धारित किया गया कि मामले की सभी परिस्थितियों के आलोक में, अवमानना, यदि कोई हो, केवल एक तकनीकी चरित्र की थी और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों की ओर से शपथ पत्र दायर किए जाने के बाद, उनके खिलाफ कार्यवाही को हटा दिया जाना चाहिए था।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः 1951 की आपराधिक अपील संख्या 24

1949 के आपराधिक विविध मामले संख्या 34 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 5 मई, 1950 के निर्णय और आदेश से 2 अप्रैल, 1951 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति द्वारा अपील।

एम. सी. सीतलवाड़, भारत के महान्यायवादी, के. एस. कृष्णवर्णी अयंगर और एस. पी. सिन्हा (वी. एन. सेठी, के. बी. अस्थाना, एन. जी. सेन, के. एन. अग्रवाल, शौकत हुसैन, के. पी. गुप्ता, एम. डी. उपाध्याय और जी. माथुर, उनके साथ) अपीलार्थियों के लिए।

प्रतिवादी के लिए गोपालजी मेहरोत्रा और जगदीश चंद्र।

1953, 8 मई

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था-

जे. मुखर्जिया

विशेष अवकाश पर हमारे समक्ष आई यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के 5 मई, 1950 के एक फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान न्यायाधीशों ने अपीलार्थियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। और यद्यपि अपीलार्थियों द्वारा दी गई माफी स्वीकार कर ली गई थी, उन्हें प्रतिवादी राज्य की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

अपीलार्थी, जिनकी संख्या छह है, उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ़्फ़रनगर में जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्य हैं और 20 अप्रैल, 1949 को समिति द्वारा पारित कुछ प्रस्तावों के कारण उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिनकी प्रतियां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपीलार्थी नं. 1 द्वारा हस्ताक्षरित एक आवरण पत्र द्वारा जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को भेजी गई थीं।

इस अपील में उठाए गए तर्कों की सराहना करने के लिए, कुछ प्रासंगिक तथ्यों को बताना आवश्यक होगा। अवमानना कार्यवाही का आधार बनने वाले प्रस्ताव दो न्यायिक अधिकारियों के आचरण से संबंधित हैं, जो दोनों संबंधित समय पर मुजफ्फरनगर में कार्य करते थे। उनमें से एक का नाम कन्हैयालाल मेहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट था जबकि दूसरा नाम लालता प्रसाद राजस्व अधिकारी था। ऐसा कहा जाता है कि

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पहले अपीलार्थी को इन अधिकारियों द्वारा अपनी अदालतों में मामलों को दर्ज करने और वकीलों और वादी जनता के प्रति व्यवहार करने के तरीके के बारे में कई शिकायतें मिलीं। एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने मामले को हाथ में लिया और खुद को संतुष्ट करने के बाद कि शिकायतें वैध और अच्छी तरह से आधारित थीं, उन्होंने 20 अप्रैल, 1949 को एक बैठक की, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गएः -

यह निर्णय लिया गया कि-"जबकि एसोसिएशन के सदस्यों को न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कन्हय लाल और राजस्व अधिकारी श्री लालता प्रसाद के न्यायिक कार्यों के बारे में राय बनाने का पर्याप्त अवसर मिला है,

अब यह उनकी सुविचारित राय है कि दोनों अधिकारी कानून में पूरी तरह से अक्षम हैं, अपने न्यायिक कार्यों में विश्वास पैदा नहीं करते हैं, आदेश पारित करते समय गलत तथ्यों को बताने के लिए दिए जाते हैं और वादी जनता और वकीलों के लिए समान रूप से कठोर और अपमानजनक होते हैं। उपरोक्त दोनों दोषों के अलावा, अन्य दोषों को अलग-अलग सूचीबद्ध किया गया है जो नीचे दिए गए हैंः -

(प्रत्येक अधिकारी के खिलाफ शिकायतों को अलग-अलग विशिष्ट शीर्षों के तहत निर्धारित किया गया था)।

आगे यह संकल्प लिया गया कि प्रस्ताव की प्रतियां माननीय प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजी जाएं; संकल्प लिया गया कि जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर से अनुरोध किया जाए कि वे इस संबंध में निम्नलिखित लोगों की प्रतिनियुक्ति से जल्द से जल्द मिलें; "

(5 सदस्यों के नाम जिनका प्रतिनियुक्ति बनाना था, उनका उल्लेख किया गया था।

यह विवादित नहीं है कि बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की यह बैठक कैमरे में आयोजित की गई थी और इसमें किसी भी गैर-सदस्य को उपस्थित होने की अनुमति नहीं थी। प्रस्ताव स्वयं राष्ट्रपति द्वारा टाइप किए गए थे और कार्यवाही को एसोसिएशन की मिनट बुक में दर्ज नहीं किया गया था। अगले दिन, यानी 21 अप्रैल, 1949 को राष्ट्रपति ने प्रस्तावों की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर को "गोपनीय" चिह्नित एक आवरण पत्र के साथ भेजी। प्रस्तावों की प्रतियां इसी तरह डिवीजन के आयुक्त, मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री को भेजी गईं। यह विवादित नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट संबंधित अधिकारियों में तत्काल श्रेष्ठ था, और अन्य तीन आधिकारिक पदानुक्रम में उच्च कार्यकारी अधिकारी थे। इस आवरण पत्र के एक पैराग्राफ में निम्नलिखित कथन थाः

"इन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें बढ़ रही थीं और एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जब मामले को औपचारिक रूप से उठाया जाना था। यह प्रस्ताव न केवल सुविचारित और सर्वसम्मत है, बल्कि आपराधिक और राजस्व पक्ष के सभी पेशेवरों की राय की सर्वसम्मति का प्रतिनिधित्व करता है।

जिला मजिस्ट्रेट को संबोधित पत्र के पोस्ट-स्क्रिप्ट में एक प्रार्थना थी कि उन्हें तीसरे प्रस्ताव में बताए अनुसार 5 सदस्यों की प्रतिनियुक्ति से मिलने के लिए जल्द से जल्द तारीख तय करना सुविधाजनक लगे।

संभागीय आयुक्त ने 27 अप्रैल, 1949 को अपीलार्थी संख्या 1 को संबोधित अपने पत्र में प्रस्तावों की प्रति की प्राप्ति को स्वीकार किया और प्राप्तकर्ता से अनुरोध किया कि वे प्रस्ताव में निहित आरोपों के समर्थन में इन अधिकारियों द्वारा परीक्षण किए गए मामलों का विशिष्ट विवरण प्रदान करें। हालाँकि, इस जानकारी की प्रतीक्षा किए बिना, अगले दिन आयुक्त ने यू. पी. सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा जिसमें सुझाव दिया गया कि इस मामले को उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे उदाहरण दुर्लभ नहीं थे जहां बार के प्रभावशाली सदस्यों ने न्यायिक अधिकारियों पर अतिरिक्त-न्यायिक दबाव डालने के उद्देश्य से अपने संघों द्वारा इस तरह के प्रस्ताव पारित कराए ताकि वे उनकी इच्छाओं के प्रति उत्तरदायी हो सकें जो अक्सर संदिग्ध थे। 10

मई, 1949 को 5 सदस्यों की प्रतिनियुक्ति ने जिला मजिस्ट्रेट का इंतजार किया और उनके साथ पूरी स्थिति पर चर्चा की। मजिस्ट्रेट ने प्रतिनियुक्ति से यह भी कहा कि आयुक्त द्वारा आवश्यक शिकायतों का विवरण जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये विवरण 20 जून, 1949 को अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को भेजे गए थे और विशिष्ट उदाहरणों का हवाला दिया गया था, जिनकी सटीकता की पुष्टि कई वरिष्ठ वकीलों द्वारा की गई थी जिन्होंने वास्तव में उन मामलों का संचालन किया था। 20 जुलाई, 1949 को जिला मजिस्ट्रेट ने संभागीय आयुक्त के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पंजीयक को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे 20 अप्रैल, 1949 को पारित प्रस्तावों और समिति के सदस्यों द्वारा की गई अन्य टिप्पणियों की ओर उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करें और सुझाव दें कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम 1926 की धारा 3 के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। 16 नवंबर, 1949 को उच्च न्यायालय ने समिति के 8 सदस्यों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि वे कारण बताए कि प्रस्ताव के कुछ हिस्सों के संबंध में अदालत की अवमानना के लिए उनसे क्यों नहीं निपटा जाना चाहिए, जो नोटिस में निर्धारित किए गए थे। इन नोटिसों के जवाब में, विरोधी पक्ष उपस्थित हुए और हलफनामे दायर किए। इस मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ ने की, जो 5 मई, 1950 के अपने फैसले से इस निष्कर्ष पर

पहुंचे कि दो विरोधी पक्षों को छोड़कर, जो संबंधित तिथि पर कार्यकारी समिति के सदस्य नहीं थे, शेष छह अदालत की अवमानना के दोषी थे। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विरोधी पक्ष किसी व्यक्तिगत या अनुचित उद्देश्य से प्रेरित नहीं थे; उनकी ओर से दिया गया बयान कि उनका उद्देश्य हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि न्याय के प्रशासन में सुधार करना था, अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी यह देखा गया कि प्रस्ताव में उपयोग किए गए शब्दों को व्यक्तिगत दुर्व्यवहार से बहुत कम हटा दिया गया था और जो भी उद्देश्य हो सकता था, वे स्पष्ट रूप से मजिस्ट्रेट को अवमानना में लाने और अपने अधिकार को कम करने की संभावना रखते थे। निर्णय का समापन भाग इस प्रकार हैः

"हम सोचते हैं कि विरोधी पक्षों ने स्थिति के बारे में एक गलतफहमी के तहत काम किया, लेकिन उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया है और एक अयोग्य माफी मांगी है। इन परिस्थितियों में, हम उनकी माफी स्वीकार करते हैं, लेकिन हम निर्देश देते हैं कि वे सरकारी अधिवक्ता की लागत का भुगतान करें, जिसका हम अनुमान रु। 300 करते है।"

यह इस फैसले का औचित्य है जिस पर इस अपील में हमारे सामने हमला किया गया है।

उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के अनुसार, वर्तमान मामले में न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अवमानना की श्रेणी में आते हैं जो "अदालत को बदनाम" करके किया जाता है। विद्वान न्यायाधीशों ने विनियमन बनाम ग्रे (') में लॉर्ड रसेल की घोषणा के अधिकार पर टिप्पणी की कि अवमानना का यह वर्ग एक महत्वपूर्ण योग्यता के अधीन है। न्यायाधीश और अदालतें समान रूप से आलोचना के लिए खुली हैं और यदि किसी भी न्यायिक कार्य के खिलाफ उचित तर्क या व्याख्या की जाती है जो कानून या सार्वजनिक भलाई के विपरीत है, तो कोई भी अदालत इसे अदालत की अवमानना के रूप में नहीं मान सकती है। विद्वान न्यायाधीशों की राय में, अपीलकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायत निष्पक्ष और वैध आलोचना की सीमा को पार कर गई और इस संबंध में बार एसोसिएशन के सदस्य आम नागरिकों की तुलना में किसी भी उच्च विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य के कारण भी कोई अंतर नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आरोप उन अधिकारियों को किए गए अभ्यावेदन में सन्निहित थे जो संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक वरिष्ठ थे और जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में बाद वाले ने कार्य किया था।

अपील के समर्थन में पेश हुए विद्वान महान्यायवादी ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के इस तरीके को पूरी तरह से गलत बताया। उनका तर्क है कि कोई भी कार्य या प्रकाशन जिसकी गणना किसी न्यायाधीश के अधिकार या गरिमा को कम करने के लिए की जाती है, वह स्वयं न्यायालय की अवमानना नहीं है। परीक्षण यह है कि क्या आरोप ऐसे चरित्र के हैं या ऐसी परिस्थितियों में लगाए गए हैं जो न्याय के मार्ग या कानून के उचित प्रशासन में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखते हैं. इस संबंध में उनके द्वारा न्यायिक समिति की कुछ घोषणाओं पर भरोसा रखा गया था, जिसमें निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायाधीश के चरित्र या आचरण को प्रभावित करने वाला कोई आरोप, भले ही वह मानहानि की कार्यवाही का विषय हो, आवश्यक रूप से अदालत की अवमानना के बराबर नहीं होगा। महान्यायवादी ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि पारित प्रस्ताव और वर्तमान मामले में अपीलार्थियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन संबंधित अधिकारियों की कथित कमियों को जनता के सामने उजागर करने के उद्देश्य से नहीं थे। पूरा उद्देश्य वकीलों और मुकदमेबाजी करने वाली जनता की शिकायतों को दूर करना था जो वास्तव में महसूस की गई थीं, अधिकारियों से अपील करके जो अकेले उन्हें हटाने के लिए सक्षम थे। यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह के आचरण को किसी भी तरह से कानून के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं माना जा

सकता है और इसे अदालत की अवमानना नहीं माना जा सकता है। उठाए गए बिंदु निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं और उनकी सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

यह किसी भी विवाद को स्वीकार नहीं करता है कि अपने अधिकार की अवमानना को दंडित करने में वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली संक्षिप्त क्षेत्राधिकार न्याय के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप को रोकने और अदालतों में प्रशासित कानून के अधिकार को बनाए रखने के उद्देश्य से मौजूद है। यह केवल वही दोहराना होगा जो विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा इतनी बार कहा गया है कि अवमानना कार्यवाही का उद्देश्य न्यायाधीशों को व्यक्तिगत रूप से उन आरोपों से सुरक्षा प्रदान करना नहीं है जिन पर वे व्यक्तिगत रूप से उजागर हो सकते हैं; इसका उद्देश्य जनता के लिए एक सुरक्षा होना है जिनके हित बहुत अधिक प्रभावित होंगे यदि किसी भी पक्ष के कार्य या आचरण से न्यायालय का अधिकार कम हो जाता है और उसके द्वारा न्याय के प्रशासन में लोगों का विश्वास कमजोर हो जाता है।

वास्तव में ऐसे असंख्य तरीके हैं जिनके द्वारा न्यायालयों में न्याय के उचित प्रशासन में बाधा डालने या बाधा डालने के प्रयास किए जा सकते हैं। इस तरह का एक प्रकार का हस्तक्षेप उन मामलों में पाया जाता है जहां कोई अधिनियम या प्रकाशन होता है जो "अदालत को

बदनाम करने के बराबर होता है-एक ऐसी अभिव्यक्ति जो लॉर्ड हार्डविक (') के दिनों से अंग्रेजी वकीलों के लिए परिचित है। यह अपमान विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, लेकिन वास्तव में, यह व्यक्तिगत न्यायाधीशों या समग्र रूप से अदालत पर विशेष मामलों के साथ या बिना संदर्भ के हमला है, जो न्यायाधीशों के चरित्र या क्षमता पर अनुचित और मानहानिकारक आक्षेप लगाता है। इस तरह के आचरण को इस कारण से अवमानना के रूप में दंडित किया जाता है कि यह लोकप्रिय दिमाग में अविश्वास पैदा करता है और अदालतों में लोगों के विश्वास को कम करता है जो वादियों के लिए उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा में प्रमुख महत्व रखते हैं।

प्रारंभिक काल से अंग्रेजी अदालतों के निर्णय ऐसे हैं जहां अदालतों ने उन व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबद्ध कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया था जो अदालत के संबंध में किसी भी निंदनीय मामले को प्रकाशित करने के दोषी थे। वर्ष 1899 में, लॉर्ड मॉरिस ने 211 एकलोड बनाम सेंट ऑबिन (') में न्यायिक समिति का निर्णय देते हुए कहा कि "अदालत को बदनाम करके अवमानना के लिए किए गए अपराध इस देश में अप्रचलित हो गए हैं। अदालतें जनमत हमलों या उनके लिए अपमानजनक या निंदनीय टिप्पणियों को छोड़ने के लिए संतुष्ट हैं। उनके लॉर्डशिप ने आगे कहाः "न्याय के उचित प्रशासन के लिए अवमानना के

लिए संक्षेप में करने की शक्ति आवश्यक मानी जाती है। इसका उपयोग एक व्यक्ति के रूप में न्यायाधीश की पुष्टि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उसे मानहानि या आपराधिक जानकारी के लिए कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए।

लॉर्ड मॉरिस का यह अवलोकन कि अदालतों को बदनाम करने के लिए अवमानना की कार्यवाही इंग्लैंड में अप्रचलित हो गई है, कड़ाई से कहें तो सही नहीं है। क्योंकि, अगले ही वर्ष, ऐसी कार्यवाही विनियमन बनाम ग्रे (') में की गई थी। उस मामले में, डार्लिंग जे., जो उस समय बर्मिंघम एसेज़ में बैठे थे और वेल्स नाम के एक व्यक्ति पर मुकदमा चला रहे थे, पर एक अपमानजनक हमला किया गया था, जिन पर अश्लील साहित्य बेचने और प्रकाशित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया था।

न्यायाधीश ने मुकदमे के दौरान समाचार पत्र प्रेस को चेतावनी दी कि अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते समय, उनके लिए मुकदमे के दौरान सामने आए अश्लील मामलों का प्रचार करना उचित नहीं था। इस पर, प्रतिवादी ने बर्मिंघम डेली आर्गस में "एन एडवोकेट्स ऑफ डिसेंसी" शीर्षक के तहत एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें डार्लिंग जे. को अभद्र भाषा में गाली दी गई थी। "तब कुओं का मामला खत्म हो गया था लेकिन सहायक अभी भी बैठे थे. इसमें कोई संदेह नहीं हो

सकता कि प्रकाशन अदालत की अवमानना के बराबर था और इस तरह के हमले की गणना न्याय के उचित प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप करने के लिए की गई थी। हालाँकि, लॉर्ड रसेल ने अपने निर्णय के दौरान इस बात का ध्यान रखा कि ऐसे मामलों में अवमानना कार्यवाही के माध्यम से संक्षिप्त अधिकार क्षेत्र का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और केवल तभी जब मामला स्पष्ट और उचित संदेह से परे हो। "क्योंकि", जैसा कि उनके लॉर्डशिप ने कहा, "यदि यह उचित संदेह से परे मामला नहीं है, तो अदालत को महान्यायवादी को आपराधिक जानकारी के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए छोड़ना चाहिए। 1943 में, लॉर्ड एटकिन ने देवी प्रसाद बनाम राजा सम्राट (') मामले में प्रिवी काउंसिल का निर्णय देते हुए कहा कि अवमानना के मामले, जिनमें अदालत को ही बदनाम करना शामिल है, सौभाग्य से दुर्लभ हैं और इन्हें बहुत विवेक के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। अवमानना की इस प्रजाति के लिए कार्यवाही का उपयोग न्याय के प्रशासन के संदर्भ में संयम से और हमेशा किया जाना चाहिए। "यदि किसी न्यायाधीश को इस तरह से बदनाम किया जाता है कि न्याय के प्रशासन को प्रभावित न करे, तो उसके पास मानहानि के लिए सामान्य उपाय जे हैं यदि वह उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित महसूस करता है।"

इसलिए, ऐसा लगता है कि दो प्राथमिक विचार हैं जो अदालत के साथ विचार करने चाहिए जब उसे अदालत को "बदनाम" करके की गई अवमानना के मामले में संक्षिप्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। सर्वप्रथम, अपने न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किसी न्यायाधीश के आचरण या चरित्र पर प्रतिबिंब अवमानना नहीं होगी यदि ऐसा प्रतिबिंब निष्पक्ष और उचित आलोचना के अधिकार के प्रयोग में किया जाता है जो प्रत्येक नागरिक के पास न्याय के स्थान पर किए गए सार्वजनिक कार्यों के संबंध में है। आलोचना को दबाने से अदालतों में विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता है। लॉर्ड एटकिन (') ने कहा, "आलोचना का मार्ग एक सार्वजनिक तरीका है। गलत सिर वाले लोगों को इसमें गलती करने की अनुमति है; बशर्ते कि जनता के सदस्य न्याय के प्रशासन में भाग लेने वालों पर उद्देश्यों को थोपने से दूर रहें और वास्तव में आलोचना के अधिकार का प्रयोग कर रहे हों और द्वेष में कार्य नहीं कर रहे हों, या न्याय के प्रशासन को बाधित करने का प्रयास नहीं कर रहे हों, वे स्वतंत्र हैं।

दूसरा, जब किसी न्यायाधीश या न्यायाधीश पर हमले या टिप्पणियां की जाती हैं, चरित्र में अपमानजनक और उनकी गरिमा के लिए अपमानजनक होती हैं, तो न्यायाधीश पर मानहानि क्या है और वास्तव में अदालत की अवमानना के बराबर क्या है, इसके बीच अंतर

करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। यह तथ्य कि जहाँ तक न्यायाधीश का संबंध है, एक बयान मानहानिकारक है, आवश्यक रूप से इसे अवमानना नहीं बनाता है। मानहानि और अवमानना के बीच का अंतर प्रिवी काउंसिल की एक समिति द्वारा इंगित किया गया था, जिसके लिए 1892 (2) में राज्य सचिव द्वारा एक संदर्भ दिया गया था। बहामा द्वीप समूह के एक व्यक्ति ने एक औपनिवेशिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक पत्र में कॉलोनी के मुख्य न्यायाधीश की बेहद गलत तरीके से चुनी गई भाषा में आलोचना की जो व्यंग्यात्मक और तीखी थी। एक परोक्ष आक्षेप था कि वह एक अक्षम न्यायाधीश और काम में एक झटकेदार व्यक्ति थे और लेखक ने इस तरह से सुझाव दिया कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो यह एक आकस्मिक बात होगी। 11 सदस्यों के एक मजबूत बोर्ड ने बताया कि शिकायत किए गए पत्र, हालांकि इसे मानहानि के लिए कार्यवाही का विषय बनाया गया था, परिस्थितियों में, न्याय के पाठ्यक्रम या कानून के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं सोचा गया था और इसलिए यह अदालत की अवमानना का गठन नहीं करता था। ऊपर उल्लिखित देवी प्रसाद बनाम राजा सम्राट (3) के मामले में लॉर्ड एटकिन द्वारा इसी सिद्धांत को दोहराया गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने राजा बनाम निकोल्स (') मामले में इसे मंजूरी दी और इस अदालत ने रेड्डी बनाम मद्रास राज्य (1) मामले में इसे ध्वनि के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए स्थिति

यह है कि जहां तक न्यायाधीश का संबंध है, एक न्यायाधीश पर मानहानिकारक हमला एक मानहानि हो सकती है और यदि वह चाहे तो मानहानिकारक के खिलाफ उचित कार्रवाई में आगे बढ़ने के लिए उसके लिए खुला होगा। हालाँकि, यदि अपमानजनक बयान के प्रकाशन की गणना ऐसे न्यायालय द्वारा न्याय के उचित पाठ्यक्रम या कानून के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए की जाती है, तो इसे अवमानना के रूप में संक्षेप में दंडित किया जा सकता है। एक न्यायाधीश के साथ व्यक्तिगत रूप से की गई गलती है जबकि दूसरी जनता के साथ की गई गलती है। यह जनता के लिए एक चोट होगी यदि यह न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा, क्षमता या निष्पक्षता के बारे में लोगों के मन में आशंका पैदा करता है या वास्तविक और संभावित वादियों को न्यायालय के न्याय प्रशासन पर पूरी तरह से भरोसा करने से रोकता है, या यदि यह न्यायाधीश के मन में अपने न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदगी पैदा करने की संभावना है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सकारात्मक रूप से यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि इस तरह के मानहानिकारक बयान के कारण न्याय के प्रशासन में वास्तविक हस्तक्षेप हुआ है; यह पर्याप्त है यदि यह कानून के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने की संभावना है, या किसी भी तरह से है (2)

इन सिद्धांतों के आलोक में हम वर्तमान सी के तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

यह विवादित नहीं हो सकता कि अवमानना के मामलों के संबंध में, बार एसोसिएशन के सदस्य आम नागरिकों की तुलना में किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त या उच्च पद पर नहीं हैं। जिस रूप में अपमानजनक बयान दिया गया है वह भी भौतिक नहीं है, लेकिन हमारे सामने मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्थात, यह मानते हुए भी कि बयान न्यायिक अधिकारियों की गरिमा के लिए अपमानजनक था, इस बयान का बहुत कम प्रचार किया गया था, और वास्तव में, अपीलकर्ताओं ने इस बात को जनता की जानकारी से बाहर रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। 4 निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया गया था जो संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक वरिष्ठ थे; और उच्च न्यायालय द्वारा यह एक तथ्य के रूप में पाया गया है कि अपीलकर्ताओं ने न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखते हुए ईमानदारी से काम किया, हालांकि वे सटीक कानूनी स्थिति के बारे में गलतफहमी में हो सकते हैं। प्रस्ताव की कोई प्रति संबंधित अधिकारियों को भी नहीं भेजी गई थी। अपीलार्थियों द्वारा अभ्यावेदन की सामग्री और उसमें उपयोग की गई भाषा के अलावा, इस

तथ्य का इस प्रश्न पर प्रभाव पड़ेगा कि क्या अपीलार्थियों का आचरण उन्हें अवमानना कानून के दायरे में लाता है।

पहला सवाल जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या दो न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ किए गए आरोप लगाने में, अपीलकर्ताओं ने निष्पक्ष और वैध आलोचना की सीमाओं को पार किया है। बैठक में तीन प्रस्ताव पारित किए गए; दूसरा और तीसरा केवल एक औपचारिक चरित्र का था और इसमें किसी भी विचार की आवश्यकता नहीं थी। अपमानजनक कथन पहले संकल्प में पाया जाता है जो फिर से दो भागों में होता है। पहले भाग में, दोनों अधिकारियों के खिलाफ सामान्य प्रकृति के आरोप हैं, लेकिन दूसरे भाग में विशिष्ट शीर्षों के तहत उन शिकायतों को गिना गया है जो समिति ने उनमें से प्रत्येक के खिलाफ अलग-अलग की थीं।

जहां तक कन्हैया लाल का संबंध है, आरोप यह है कि वह अपने द्वारा चलाए गए मामलों में साक्ष्य को ठीक से दर्ज नहीं करता है, कि उसकी अदालत में स्थानांतरित किए गए सभी आपराधिक मामलों में, जहां आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं, वह उन्हें नए सिरे से जमानत देने के लिए समय नहीं देता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जेल भेजा जाता है, और अंत में, कि वह वकीलों को बिल्कुल भी समायोजित नहीं कर रहा है। जहाँ तक दूसरे अधिकारी का संबंध है, एक गंभीर आरोप

यह लगाया गया है कि वह एक ही समय में दो मामलों की सुनवाई करने की अत्यधिक अवैध प्रक्रिया का पालन करता है, और जब वह एक मामले में स्वयं साक्ष्य दर्ज करता है, तो वह कोर्ट रीडर को दूसरे में काम करने की अनुमति देता है। यह भी कहा जाता है कि वह गुस्से में है और अक्सर वकीलों को अवमानना की कार्यवाही की धमकी देता है। इनमें से कुछ शिकायतें बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं और कोई भी न्यायाधीश, जब तक कि वह अतिसंवेदनशील नहीं है, उनसे बिल्कुल भी व्यथित नहीं होगा। यह निस्संदेह एक गंभीर आरोप है कि राजस्व अधिकारी एक साथ दो मामलों की सुनवाई करता है और कोर्ट रीडर को उसके लिए काम करने की अनुमति देता है। यह सच है कि यह एक पेटेंट अवैध है और सटीक रूप से एक ऐसा मामला है जिसे जिला मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाया जाना चाहिए जो इन अधिकारियों के प्रशासनिक प्रमुख हैं।

जहां तक प्रस्ताव के पहले भाग का संबंध है, आरोप सामान्य शब्दों में लगाए जाते हैं कि ये अधिकारी आदेश पारित करते समय तथ्यों को सही ढंग से नहीं बताते हैं और वे वादी जनता के लिए अपमानजनक हैं। ये किसी भी तरह से अदालत को बदनाम करने के बराबर नहीं हैं। इस तरह की शिकायतों को अक्सर कई अधीनस्थ अदालतों के संबंध में सुना जाता है और यदि अपीलकर्ताओं की

वास्तविक शिकायत थी, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अपनी शिकायतों को उजागर करने में उन्होंने निष्पक्ष आलोचना की सीमाओं को पार कर लिया था।

प्रस्ताव का एकमात्र हिस्सा जिस पर प्रथम दृष्टया आपत्ति की जा सकती है, वह है जो इन अधिकारियों को कानून में पूरी तरह से अक्षम बताता है और जिनका न्यायिक कार्य विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। ये टिप्पणियां निश्चित रूप से व्यापक प्रकृति की हैं और इन्हें शायद ही उचित ठहराया जा सकता है। हालाँकि, यह मानते हुए कि प्रस्ताव का यह हिस्सा मानहानिकारक है, सवाल उठता है कि क्या इसे अदालत की अवमानना माना जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें यह देखना होगा कि क्या यह किसी भी तरह से इन अदालतों में न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए सोचा गया है, या दूसरे शब्दों में, क्या इस तरह के बयान से वादियों के मन में आशंका पैदा होने की संभावना है कि दोनों न्यायिक अधिकारी अपने सामने आने वाले मामलों से ठीक से निपट सकते हैं, या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में खुद अधिकारियों को शर्मिंदा कर सकते हैं।

'वे प्रत्यर्थी के विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए अभ्यावेदन की गणना इन परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए की जाती है या नहीं, यह केवल

और विशेष रूप से संकल्पों की भाषा या सामग्री के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है; और यह कि इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य तथ्य या परिस्थिति पर विचार नहीं किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जो अवमानना के अपराध को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, यदि ऐसा अपराध किया गया है। ऐसा हो सकता है कि औचित्य या विशेषाधिकार की दलीलें अवमानना कार्यवाही में प्रतिवादी के लिए सख्ती से उपलब्ध नहीं हैं।

तकनीकी अर्थों में भी प्रकाशन का प्रश्न जिसमें यह मानहानि की कार्रवाई में प्रासंगिक है, अवमानना के कानून के लिए अनुचित हो सकता है। लेकिन, प्रत्यक्ष अवमानना के मामलों को छोड़ते हुए, जहां यह सवाल उठता है कि क्या किसी न्यायाधीश के खिलाफ निर्देशित मानहानिकारक बयान की गणना न्यायाधीश की क्षमता या अखंडता में जनता के विश्वास को कम करने के लिए की जाती है, या अदालत को अपने कर्तव्यों के सख्त और अडिग प्रदर्शन से विचलित करने की संभावना है, आसपास के सभी तथ्य और परिस्थितियां जिनके तहत बयान दिया गया था और इसे दिए गए प्रचार की मात्रा निस्संदेह प्रासंगिक परिस्थितियां होंगी। यह सच है क्योंकि प्रतिवादी के विद्वान वकील का सुझाव है कि इस मामले पर वर्तमान मामले में बी. टी. यू. के सदस्यों के बीच चर्चा की गई थी, और यह उन अधिकारियों के बीच भी चर्चा का विषय हो सकता है जिन्हें

प्रस्तावों की प्रतियां भेजी गई थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा प्रकाशन था जो मानहानि के कानून द्वारा आवश्यक है, लेकिन अवमानना कार्यवाही में, जो किसी भी तरह से निर्णायक नहीं है। सामग्री यह है कि प्रकाशन की प्रकृति और विस्तार क्या है और क्या इसका जनता या स्वयं न्यायपालिका के दिमाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना थी या नहीं और इस तरह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप होता है। हमारे सामने मौजूद सामग्रियों पर, यह कहना मुश्किल है कि जिन परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, उनका ऐसा प्रभाव था। कुछ दूर की संभावना हो सकती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। हमारा स्पष्ट मत है कि अवमानना, यदि कोई हो, केवल एक तकनीकी चरित्र की थी, और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों की ओर से हलफनामे दायर किए जाने के बाद, उनके खिलाफ कार्यवाही को हटा दिया जाना चाहिए था। परिणाम यह है कि अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है. यहां या नीचे की अदालत में किसी भी पक्ष के पक्ष में खर्च के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

अपीलार्थियों के लिए अभिकर्ताः एस. एस. शुक्ला

उत्तरदाताओं के लिए अभिकर्ताः सी पी लाल

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक मनीष शर्मा द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।